कुशल भारत अगले 5 वर्षों में इसरो के 4000 तकनीकी कर्मचारियों को कौशल उन्नयन प्रदान करेगा

- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसरो तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया
- प्रशिक्षण बैंगलोर, चेन्नई, कालीकट, हैदराबाद और मुंबई एनएसटीआई में शुरू होगा





नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कर्मचारियों को कौशल उन्नयन प्रदान करने के उद्देश्य से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर श्री राजेश अग्रवाल, सचिव एमएसडीई और श्री एस. सोमनाथ, सचिव अंतरिक्ष विभाग/अध्यक्ष इसरो द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार इसरो के तकनीकी कर्मचारियों के कौशल विकास और क्षमता-निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करना है। इस कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों के दौरान 4000 से अधिक इसरो तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का स्थान भारत भर में स्थित एमएसडीई के तहत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) होंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अंतिरक्ष विभाग (डीओएस) के तहत इसरो केंद्रों और इकाइयों में काम करने वाले विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ावा देना है। देश भर में एमएसडीई और इसके अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से, कार्यक्रम नवीनतम उद्योग पद्धितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों के कौशल को उन्नत करने के लिए विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। एमओयू के तहत, इसरो कार्यक्रम के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण कैलेंडर, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए एमएसडीई और संबद्ध एनएसटीआई के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा। इसरो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण किट उपलब्ध कराएगा।

इसके साथ, एमएसडीई क्षमता-निर्माण कार्यक्रम कार्यालय (सीबीपीओ) के परामर्श से अभिज्ञात राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, कक्षाओं, नमूनों और अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा। एमएसडीई इसके सफल निष्पादन के लिए समग्र प्रबंधन और कार्यक्रम के पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार होगा।

एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कहा, "प्रौद्योगिकी के आगमन और दुनिया के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के साथ, यह जरूरी है कि हम अपने तकनीकी कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में कुशल बनाएं। इसरों में तकनीकी विशेषज्ञों का कौशल उन्नयन उसी दिशा में एक कदम है। पिछले दस वर्षों में बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष डोमेन को फिर से परिभाषित करने की बात आती है तो इसरों एक गेम-चेंजर रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी कर्मियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने और बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचा उठाया जा सकेगा। हम उनकी सफलता में योगदान देने के लिए तत्पर हैं क्योंकि वे भारत के लिए अंतरिक्ष का एक नया भविष्य तैयार करते हैं।

श्री टीवीएलएन राव, आरडी, आरडीएसडीई, कर्नाटक; श्री कुमारवेल, डीडी, आरडीएसडीई, कर्नाटक; श्री सी रिव, निदेशक, सीएफआई, डीजीटी; श्री परवीन कुमार, डीडी, डीजीटी; श्री मनीष गुप्ता, सहायक निदेशक, एमएसडीई; एन. सुधीर कुमार, निदेशक, सीबीपीओ, इसरो; और निशांत कुमार, उप निदेशक, इसरो की उपस्थिति में तुरंत प्रभाव से लागू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह 5 वर्ष की अविध के लिए वैध होगा।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के बारे में

एमएसडीई का गठन 9 नवंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा कौशल की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, एमएसडीई ने नीति, रूपरेखा और मानकों को औपचारिक रूप देने; नए कार्यक्रमों और स्कीमों का शुभारंभ; नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन; राज्यों के साथ भागीदारी; उद्योगों से जुड़ना और कौशल के लिए सामाजिक स्वीकृति और आकांक्षाओं का निर्माण करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल और सुधार किए हैं। मंत्रालय का उद्देश्य न केवल मौजूदा जॉब्स के लिए बल्कि सृजित जॉब्स के लिए भी नए कौशल और नवाचार का निर्माण करने के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना है। कुशल भारत के तहत अब तक 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।